राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक

रोकठोक लेखनी

RNI NO. : MAHHIN/2019/77511

खबरें बे-रोकटोक

वर्ष 07 | अंक 41 | मुंबई : बुधवार 19 अगस्त 2026 से 25 अगस्त 2026 | संपादक : फैसल शेख | पृष्ठ : 8 | कीमत : 03 रुपये

चूहे-कॉकरोच और गंदगी...

मुंबई के एक और होटल में FDA का छापा, लाइसेंस सस्पेंड

मुंबई। महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मुंबई के एक और होटल का फूड बिजनेस लाइसेंस सस्पेंड करने का आदेश दिया है। जांच में पाया गया कि होटल की रसोई में चूहे और कॉकरोच भरे हुए थे। 18 अगस्त को हुई छापेमारी के बाद मलाड (पश्चिम) में स्थित 'होटल राधा' का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया।

निरीक्षण के दौरान चूहों का भारी उपद्रव पाया गया; छत के पास और रसोई की खुली ड्रेनेज लाइनों से सीधे निकलते हुए जिंदा चूहे देखे गए।

मुंबई के होटल राधा का फूड लाइसेंस सस्पेंड

किचन के ड्रेन पूरी तरह खुले थे, जिससे सीवेज के कीड़े-मकोड़ों के अंदर आने का सीधा रास्ता बन गया था। जांच के दौरान इंस्पेक्टरों ने देखा कि कॉकरोच सीधे खाना बनाने वाले सामानों पर घूम रहे थे। पूरे किचन में साफ-सफाई का बुरा हाल था, पानी जमा होने, ग्रीस जमने और ड्रेन से रिसाव के कारण बदबू आ रही थी। जांच के दौरान लिए गए वीडियो और तस्वीरों में एक बेहद गंदी रसोई दिखाई दी, जो तेल और चिकनाई से भरी हुई थी।

बर्तन और खाना पकाने के काउंटर पर कालिख की परतें जमी हुई थीं। सामान रखने की जगहें भी गंदी थीं।

होटल में चारों तरफ मिली गंदगी

खाने के डिब्बों और कंटेनरों पर मिट्टी और धूल लगी हुई थी। बर्तनों पर जंग लगा था, और कूड़ेदान खुला हुआ था जिसमें कचरा भरा था; उसी कूड़ेदान के ऊपर टोस्टर रखा था, जहाँ खाना बनाया जा रहा था।

तस्वीरों में खाने की सामग्री भी बहुत ही अस्वच्छ हालत में रखी हुई दिखाई दी। ऋर एक्ट, 2006 की धारा 32(3) के तहत कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने लाइसेंस सस्पेंड कर दिया।

एनफोर्समेंट ऑर्डर में 18 अगस्त से सभी मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन के काम को तुरंत बंद करने का आदेश दिया गया। यह कार्रवाई महाराष्ट्र के होटलों, रेस्टोरेंट, सरकारी कैंटीन और दूसरी जगहों पर राज्य-स्तर पर की जा रही सख्ती के बीच हुई है।

मुंबई में 210 भूतिया कर्मचारियों के नाम पर 4.15 करोड़ का बैंक घोटाला,

पूर्व CEO समेत 4 पर FIR

मुंबई : मुंबई के विले पार्ले में बैंक से जुड़े कथित बड़े लोन घोटाले का मामला सामने आया है। विले पार्ले पुलिस ने बैंक के पूर्व सीईओ समेत चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि कागजों पर 210 कथित 'भूतिया' कर्मचारियों के नाम खड़े कर उनके नाम पर कुल 4.15 करोड़ रुपये का लोन जारी कराया गया।

210 कर्मचारियों के नाम पर निकाली रकम

पुलिस के अनुसार, मुंबई पैरामेडिकल कंपनी के 126 कथित कर्मचारियों के नाम पर 2.47 करोड़ रुपये से अधिक और पीपल पैरामेडिकल कंपनी के 84 कथित कर्मचारियों के नाम पर करीब 1.68 करोड़ रुपये के लोन जारी किए गए। इस तरह 210 खातों से कुल 4,15,05,000 रुपये निकाले गए। जांच में कथित तौर पर सामने आया कि जिन लोगों के नाम पर लोन लिया गया, उन्होंने कंपनियों में कभी काम करने से इनकार किया। लोन के लिए इस्तेमाल किए गए आईडी कार्ड, वेतन पर्ची, सैलरी सर्टिफिकेट और रबर स्टैंप फर्जी पाए गए।

घर की मरम्मत के नाम पर लोन

बताया गया है कि सभी 210 मामलों में लोन लेने का कारण घर की मरम्मत बताया गया था। इसके लिए वेस्टर्न कंस्ट्रक्शन इंजीनियर और लक्ष्मी इंटीरियर के नाम से कथित फर्जी कोटेशन लगाए गए थे। लोन स्वीकृत होने के दिन ही संबंधित बचत खाते खोले गए थे।

महाराष्ट्र में 1.25 लाख ऑटो, टैक्सी ड्राइवरों ने मराठी सीखी

सरकार की इस मुहिम से यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

डिप्टी सीएम शिंदे ने जोर देकर कहा कि मराठी श्रद्धा की भाषा है न कि मजबूरी की

ठाणे। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थानीय संगठनों के सहयोग से शुरू किए गए 105-दिन के अभियान के तहत लगभग 1.25 लाख ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों ने कामचलाऊ मराठी दक्षता प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया है।

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को यह जानकारी दी। थाने में एक समारोह में, जहां गैर-मराठी पृष्ठभूमि के सफल प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए, उन्होंने जोर देकर कहा कि मराठी श्रद्धा की भाषा है न कि मजबूरी की। गैर-मराठी बोलने वाले लोगों द्वारा भाषा को स्वेच्छा से अपनाना राज्य की सांस्कृतिक एकता को दर्शाता है। शिंदे हिंदू हृदयसम्राट बालासाहेब ठाकरे मराठी भाषा पाठ्यक्रम अभियान के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। 105-दिन के इस अभियान में 1.25 लाख ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों ने मराठी सीखी और परीक्षा पास की। उन्होंने राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक की प्रशंसा की, जिन्होंने कानूनी मजबूरी के बजाय सकारात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से मराठी को बढ़ावा दिया। शिंदे ने कहा भाषा प्रेम से सीखी जाती है, कानून से नहीं। उन्होंने मराठी बोलने वालों से अपील की कि वे भाषा सीखने वाले लोगों का मजाक न उड़ाएं और इसके बजाय महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा में उनके साथ संवाद करें। तीन-डेढ़ महीने की इस पहल के दौरान 1,65,600 से अधिक परिवहन श्रमिकों ने पंजीकरण कराया था।

मुंबई में बेस्ट की बसों के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रस्ताव मंजूर...

मुंबई: आर्थिक संकट से जूझ रहे बेस्ट उपक्रम के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रस्ताव मंगलवार (18 अगस्त) को मुंबई नगर निगम की आम सभा की बैठक में पेश किया गया. शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे), इंडियन नेशनल कांग्रेस और मनसे ने इस प्रस्ताव का जोरदार विरोध किया. हालाँकि, सत्ताधारी बीजेपी, शिवसेना और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अपने बहुमत का इस्तेमाल करके इस प्रस्ताव को पास कराने में सफल रही.

प्रस्ताव का विरोध करते हुए, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) पार्टी के सीनियर कॉर्पोरेटर यशोधन फांसे ने 22 बेस्ट डिपो के प्राइवेटाइजेशन पर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि बेस्ट की जमीन प्राइवेट कंपनियों को सौंपना गलत है और इससे मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कोई आर्थिक फायदा नहीं होगा.

'बेस्ट का प्राइवेटाइजेशन करने के बजाय, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इसे बेहतर बनाने के लिए पहल करनी चाहिए. बेस्ट की जमीन दूसरों को सौंपना पूरी तरह से गलत है. सिर्फ इसलिए कि तीन डिपो दे दिए गए, क्या आप 22 और डिपो भी दे देंगे?' फांसे ने सवाल किया. उन्होंने सत्ताधारी पार्टी को इस बात पर विस्तार से चर्चा करने के लिए

एक विशेष बैठक बुलाने की चुनौती भी दी कि पिछले 25 सालों में बेस्ट के लिए असल में क्या किया गया है.

बेस्ट के निजीकरण को लेकर जनरल बॉडी मीटिंग में तीखी बहस

22 बेस्ट डिपो के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद, जनरल बॉडी मीटिंग में सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई. विपक्ष ने बेस्ट के निजीकरण का विरोध किया और मांग की कि प्रस्ताव को प्रशासन के पास वापस भेजा जाए. इसके उलट, सत्ताधारी पार्टी ने फैसले का बचाव करते हुए साफ किया कि बेस्ट की जमीन बेची नहीं जा रही है, बल्कि लीज पर दी जा रही है.

चार डिपो सौंपने से मुंबई को क्या फायदा हुआ?

कांग्रेस ग्रुप लीडर अशरफ आजमी ने एक 'श्वेत पत्र' पेश करने की मांग की, जिसमें यह बताया जाए कि चार डिपो सौंपने के पिछले फैसले से मुंबई को क्या फायदा हुआ. पहले की गई गलती को न दोहराएं. दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट कंपनियां घाटे में चल रही हैं तो हम बेस्ट डिपो क्यों सौंप रहे हैं? उन्होंने सवाल किया. उन्होंने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि बेस्ट के निजीकरण से मुंबई के लोगों में परेशानी हो रही है. शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के कॉर्पोरेटर सचिन पडवाल ने सत्ताधारी पार्टी की आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया, 'भविष्य में जब मुंबई का इतिहास लिखा जाएगा, तो उसमें दर्ज होगा कि मौजूदा शासकों ने शहर को बेच दिया और उनके नाम ब्लैकलिस्ट में आ जाएंगे.' उन्होंने मांग की कि बेस्ट का निजीकरण करने के बजाय, इसे बृहन्मुंबई नगर निगम में मिला दिया जाए और प्रशासन के सामने यह प्रस्ताव फिर से पेश किया जाए. शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के कॉर्पोरेटर सचिन पाटिल ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया. उन्होंने कहा, 'किसी दूसरी पार्टी को बेस्ट की जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत देकर हम बेस्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं.

मुंबई वर्कशॉप से 46.4 लाख की चांदी चोरी, कानपुर से पकड़ा गया मास्टरमाइंड, पुलिस एक्शन की पूरी कहानी...

मुंबई : मुंबई पुलिस ने साकीनाका इलाके की एक वर्कशॉप पर हाथ साफ करने वाले चार चोरों को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया. मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी करीब 1300 किलोमीटर दूर कानपुर से हुई. इन शातिर चोरों में वर्कशॉप का एक पुराना कर्मचारी भी शामिल था. आरोपी 22 किलो चांदी, नकदी और दो मोबाइल फोन चोरी करने के बाद फरार हो गए थे. चोरी किए गए सामान की कुल कीमत करीब 46.4 लाख रुपये बताई जा रही है.

हैरानी की बात यह है कि

वर्कशॉप में रखी चांदी किसी बाजार से नहीं खरीदी गई थी, बल्कि एक पुराने रेलवे इंजन को कबाड़ में काटते समय मिली थी. पुलिस के मुताबिक, स्क्रैप कारोबारी मोहम्मद खान (31) ने करीब 25 साल पुराने एक रेलवे इंजन को सरकारी टेंडर के जरिए दौंड रेलवे स्टेशन से खरीदा था. इंजन को कबाड़ के तौर पर वर्कशॉप में लाया गया और उसे खोलते समय उसमें से शुद्ध चांदी बरामद हुई. खान ने इस चांदी को वर्कशॉप में नकदी के साथ सुरक्षित रखा था. इसी चांदी पर आरोपियों की नजर पड़ी और उन्होंने पूरी चोरी की साजिश रच डाली. पुलिस के अनुसार, चोरी की योजना रमजान मकसूद साह (20) ने बनाई थी, जो वारदात से एक दिन पहले ही वर्कशॉप की नौकरी छोड़ चुका था. आरोप है कि इसके बाद उसने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर रात के समय वर्कशॉप में घुसने की योजना बनाई.

मुंबई : दो बिल्डरों को पजेशन ना देने की वजह से हो गई जेल

मुंबई : महाराष्ट्र के मुंबई से एक मामला सामने आया है, जिसमें दो बिल्डरों को एक फ्लैट का पजेशन ना लौटा पाने की वजह स जेल की सजा काटना पड़ेगी. इतनी ही नहीं इसके साथ दोनों को 10-10 हजार रुपये जुमार्ने के रूप में भी देना होगा.

दरअसल ये मामला मुंबई के कुर्ला स्थित स्टर्लिंग अपार्टमेंट्स का है. जहां सुनील सदानंद वैती और उनकी पत्नी कीर्ति सुनील वैती ने समीर जियाउद्दीन और सरोश खान की शिकायत कंज्यूमर फोरम में की थी. उनकी शिकायत पर आयोग ने पहले बिल्डरों को फ्लैट ए-701 का

काम पूरा करने, जरूरी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने और इसके बाद खरीदारों को फ्लैट का कानूनी कब्जा देने का आदेश दिया था.

इतना ही नहीं आयोग ने खरीदारों को बाकी 14.50 लाख रुपये और कुछ अन्य शुल्क मिलाकर पूरे 15 लाख रुपये देने को कहा था. साथ ही बिल्डरों को 16.50 लाख रुपये पर 30 अगस्त 2013 से कब्जा मिलने तक 21 प्रतिशत सालाना ब्याज देने और खरीदारों को मानसिक व शारीरिक परेशानी के लिए 1 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया था. आयोग के आदेश के कुछ समय के बाद ही खरीदारों ने दोबारा शिकायत की, कि बिल्डरों ने आयोग के आदेश का पालन नहीं किया. जिस पर बिल्डरों ने सफाई दी कि जमीन की सीमा और नियमों में बदलाव के कारण बिल्डिंग का प्लान बदलना पड़ा. उन्होंने नए प्लान और जरूरी मंजूरियों के लिए आवेदन करने की बात भी कही.

मुंबई के अंधेरी में बड़ा हादसा, बेस्ट बस ने छह वाहनों को मारी टक्कर...

मुंबई: महाराष्ट्र के अंधेरी पश्चिम के गोखले ब्रिज सिग्नल पर सोमवार दोपहर में एक बेस्ट बस ने छह वाहनों को टक्कर मार दिया। इन वाहनों में चार ऑटो-रिक्शा, एक अर्टिगा कार और एक एक्टिवा स्कूटर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना में तीन लोग घायल हो गए। तीनों घायलों को इलाज के लिए कूपर अस्पताल इलाज के भर्ती करवाया गया है। अंधेरी पुलिस स्टेशन की टीम मामले की छानबीन कर रही है। इस घटना की छानबीन कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि आज दोपहर करीब 12 बजे एक बेस्ट बस अंधेरी बस स्टेशन (पश्चिम) से वसोर्वा बस स्टेशन की ओर जा रही थी। बस यह बस ओशिवारा डिपो की है और वेट-लीज व्यवस्था के तहत संचालित की जा रही थी। बस जैसे ही गोखले ब्रिज सिग्नल पर पहुंची ,बस चालक द्वारा हैंडब्रेक हटाए जाने के बाद बस आगे बढ़ गई और सिग्नल पर खड़े छह वाहनों से टकरा गई। इस घटना में 55 वर्षीय ऑटो-रिक्शा चालक युनुश शेख , 30 वर्षीय पैदल यात्री मनोजकुमार बासुदेव और 20 वर्षीय एक्टिवा सवार अनीस निसार धारी घायल हो गए। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को कूपर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अंधेरी पुलिस स्टेशन के निर्देश पर बस को आगे की कानूनी और पुलिस कार्रवाई के लिए कुमकुम चौकी पर खड़ा कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

एसआईआर का पहला चरण पूरा, 2 करोड़ से अधिक लोगों के लिस्ट से बाहर होने की 'संभावना'

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने मंगलवार को बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2026 के पहले चरण के पूरा होने के बाद राज्य के करीब 2.07 करोड़ मतदाताओं के नाम आगामी प्रारूप मतदाता सूची (ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल) से बाहर हो सकते हैं। यह संख्या राज्य के कुल मतदाताओं का लगभग 21.15 प्रतिशत है। 30 जून से 17 अगस्त 2026 तक चले घर-घर सत्यापन अभियान के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया। महाराष्ट्र में कुल 9.78 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें से 7.71 करोड़ मतदाताओं (78.85 प्रतिशत) ने हस्ताक्षरित गणना फॉर्म जमा कर दिए। जबकि, बाकी 2.07 करोड़ मतदाता 'अप्राप्त गणना फॉर्म'

(अनकलेक्टेबल एन्यूमरेशन फॉर्म) श्रेणी में रखे गए हैं।

सीईओ कार्यालय ने इन 2.07 करोड़ मतदाताओं को एएसडीडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृतक और डुप्लीकेट) श्रेणी में वर्गीकृत किया है। इनमें 76.80 लाख (7.85 प्रतिशत) स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर चले गए, 75.52 लाख (7.72 प्रतिशत) अनुपस्थित या सत्यापन के दौरान नहीं मिले, 34.81 लाख (3.56 प्रतिशत) मृतक, 17.63 लाख (1.80 प्रतिशत) डुप्लीकेट या अन्य जगह पंजीकृत पाए गए, जबकि 2.23 लाख (0.23 प्रतिशत) अन्य श्रेणी में रखे गए हैं।

इन 2.07 करोड़ संभावित रूप से बाहर होने वाले मतदाताओं में सबसे अधिक पुणे से 28.70 लाख, ठाणे से 28.61 लाख, मुंबई उपनगर जिले से 26.63 लाख, नागपुर से 14.44 लाख, नासिक से 10.29 लाख और मुंबई शहर से 9.52 लाख मतदाता शामिल हैं। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने अभियान समाप्त होने से चार दिन पहले ही संभावित रूप से बाहर किए जाने वाले मतदाताओं की सूची जिला कलेक्टरों की वेबसाइटों पर अपलोड कर दी थी। इससे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) के माध्यम से जानकारी की जांच करने का अवसर मिला। बीएलओ को निर्देश दिए गए थे कि राजनीतिक दलों से मिलने वाले फीडबैक का सत्यापन करें और पात्र मतदाताओं को फॉर्म जमा करने का अवसर दें, ताकि अंतिम प्रारूप सूची तैयार की जा सके। 24 अगस्त 2026 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद 23 सितंबर 2026 तक नागरिक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। सीईओ कार्यालय ने बताया कि जिन नागरिकों का नाम सूची में नहीं है या जो 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे, वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

मुंबई : फाइव-स्टार होटलों से कैंटीन तक एफडीए की छापेमारी, एक्सपायर्ड खाने पर सख्ती

मुंबई: महाराष्ट्र में फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने खाद्य सुरक्षा को लेकर बड़ा अभियान शुरू किया है। फाइव-स्टार होटलों से लेकर फास्ट-फूड चेन, सरकारी कैंटीन, रेस्टोरेंट, गोदाम और किराना सप्लायर्स तक जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। जांच के दौरान कई जगह एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री, खराब स्टोरेज व्यवस्था और खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए हैं। एफडीए की कार्रवाई के बाद बड़ी मात्रा में खराब और इस्तेमाल के योग्य नहीं पाए गए खाद्य पदार्थ जब्त किए गए हैं। कई जगहों पर खाद्य सामग्री को नष्ट किया गया, किचन बंद कराए गए और गोदामों को सील करने की कार्रवाई भी की गई है। इसके अलावा कुछ प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए जाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।

इस कार्रवाई के बाद सवाल उठने लगे हैं कि होटल, रेस्टोरेंट और खाद्य आपूर्ति से जुड़े संस्थानों में ग्राहकों को किस तरह का खाना परोसा जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कर्नाटक में स्टार होटलों पर एफडीए की नजर कर्नाटक में शिकायतों के बाद एफडीए ने विशेष अभियान चलाया। इसके लिए 30 स्पेशल टीमें गठित की गईं, जिन्होंने बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की।

अगस्त के पहले सप्ताह में एफडीए की टीमों ने 26 स्टार होटलों का निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य पदार्थों के करीब 35 सैंपल भी लिए गए, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। जांच के दौरान बेंगलुरु स्थित

रैडिसन ब्लू एट्रिया होटल से बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री बरामद होने का मामला सामने आया। अधिकारियों के अनुसार, होटल से करीब 105 किलोग्राम खराब खाद्य सामग्री जब्त की गई। जब्त सामग्री में लगभग 50 किलो चिकन, 25 किलो मीट, 23 किलो मछली और 7 किलो सब्जियां शामिल थीं। अधिकारियों ने बताया कि यह सामग्री उपयोग की स्थिति में नहीं थी और इसे नष्ट कर दिया गया।

एफडीए अधिकारियों ने कहा कि होटल और रेस्टोरेंट में खाद्य सामग्री के रखरखाव, तापमान नियंत्रण, स्टोरेज व्यवस्था और एक्सपायरी डेट की जांच की जा रही है। किसी भी तरह की लापरवाही मिलने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खराब स्टोरेज और स्वच्छता पर सवाल जांच के दौरान कई स्थानों पर खाद्य सामग्री रखने के तरीके में लापरवाही सामने आई। कुछ जगहों पर खाने-पीने की चीजों को सही तापमान पर स्टोर नहीं किया गया था। वहीं कुछ प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई के मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था।

एफडीए का कहना है कि केवल एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री ही नहीं, बल्कि खराब स्वच्छता व्यवस्था भी लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती है। इसलिए जांच के दौरान किचन की सफाई, कर्मचारियों की स्वच्छता और खाद्य पदार्थों के रखरखाव की भी जांच की जा रही है। महाराष्ट्र में भी बढ़ाई गई निगरानी कर्नाटक के साथ महाराष्ट्र में भी खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। यहां होटल, रेस्टोरेंट, किराना दुकानों और खाद्य सप्लाई करने वाले गोदामों की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों और बढ़ती खाद्य खपत को देखते हुए यह अभियान और तेज किया जाएगा। खासकर ऐसे प्रतिष्ठानों पर नजर रखी जा रही है जहां बड़ी संख्या में लोगों के लिए खाना तैयार किया जाता है। ग्राहकों की सुरक्षा प्राथमिकता एफडीए अधिकारियों ने कहा कि खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करना हर होटल, रेस्टोरेंट और खाद्य विक्रेता की जिम्मेदारी है। ग्राहकों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना जरूरी है। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि यदि किसी प्रतिष्ठान में खराब भोजन, गंदगी या नियमों का उल्लंघन दिखाई देता है तो इसकी शिकायत संबंधित विभाग से करें। विशेषज्ञों के अनुसार, खराब या एक्सपायर्ड खाना खाने से फूड पॉइजनिंग, पेट संबंधी बीमारियां और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।

मुंबई: मुख्यमंत्री के अधिकार को लेकर हाईकोर्ट का अहम फैसला, मंत्रियों के फैसले बदल सकेंगे

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने 'महाराष्ट्र सरकार कार्य संचालन नियम, 2026' अधिसूचित कर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को व्यापक जनहित में किसी भी कैबिनेट मंत्री के फैसले को बदलने, संशोधित करने या रद्द करने का अधिकार दिया गया है। हालांकि, ऐसे फैसलों के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना होगा और यह प्रावधान अर्ध-न्यायिक मामलों पर लागू नहीं होगा।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार आज महाराष्ट्र सरकार कार्य संचालन नियम 2026 अधिसूचित किया गया है। इसके नए नियमों के अनुसार, मुख्यमंत्री किसी भी सरकारी विभाग से फाइल, दस्तावेज या रिकॉर्ड मंगा सकते हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर संबंधित मंत्री और विभागीय सचिव को ये दस्तावेज उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। रोजमर्रा के प्रशासनिक कामकाज के लिए विभाग अपने संबंधित मंत्रियों के प्रति जवाबदेह रहेंगे। हालांकि, नए नियमों से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के अधीन सरकार की समग्र निगरानी और प्रशासनिक नियंत्रण को अधिक स्पष्ट किया गया है। नए नियमों के तहत किसी भी विभाग को खर्च करने से पहले वित्त विभाग की मंजूरी लेना आवश्यक कर दिया गया है। साथ ही कोई सार्वजनिक हित की घोषणा करने से पहले उस पर आने वाले खर्च की पहले वित्त विभाग से मंजूरी लेनी होगी, इसके बाद इसकी घोषणा की जा सकेगी।

मुंबई को मिलेगा नया टूरिस्ट अट्रैक्शन, पनवेल के मेगा एक्वेरियम में दिखेंगे सी लायन

मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आने वाले पर्यटकों के लिए जल्द ही एक नया आकर्षण जुड़ने वाला है। मुंबई से सटे रायगढ़ जिले के पनवेल में प्रस्तावित मेगा एक्वेरियम में अब सी लायन को भी शामिल किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में पर्यटकों को समुद्री जीवों की एक नई और अनोखी दुनिया देखने को मिलेगी। यह मेगा एक्वेरियम ऐसे समय में तैयार किया जा रहा है, जब मुंबई में हम्बोल्ट पेंगुइन की लोकप्रियता पहले से ही लोगों के बीच बनी हुई है। दक्षिण कोरिया से मुंबई आए हम्बोल्ट पेंगुइन ने भायखला स्थित वीरमाता जीजाबाई भोसले बॉटनिकल गार्डन और जू में बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित किया है।

मुंबई का यह जू बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा

संचालित किया जाता है और पेंगुइन यहां का प्रमुख आकर्षण बन चुके हैं। अब सी लायन को शामिल करने की योजना के बाद समुद्री जीवों को देखने के लिए पर्यटकों के पास एक और बड़ा विकल्प उपलब्ध होगा। पनवेल में बनेगा मेगा एक्वेरियम प्रस्तावित मेगा एक्वेरियम मुंबई के पास पनवेल क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य समुद्री जीवन को करीब से समझने का अवसर देना और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना है।

एक्वेरियम में अलग-अलग समुद्री जीवों को रखने की योजना है, जिसमें सी लायन भी प्रमुख आकर्षण होगा। अधिकारियों का मानना है कि इस तरह की सुविधा विकसित होने से मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को नई गति मिलेगी। दिवाली के आसपास हो सकता है शिलान्यास महाराष्ट्र के पोर्ट्स और फिशरीज मंत्री नितेश राणे ने इस प्रोजेक्ट को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि इसके शिलान्यास समारोह की योजना दिवाली के आसपास बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार इस परियोजना को आगे बढ़ाने को लेकर गंभीर है और जल्द ही इसके निर्माण से जुड़े काम शुरू किए जा सकते हैं। मुंबई के पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा मुंबई पहले से ही देश-विदेश के पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, जुहू बीच और ऐतिहासिक स्थलों के अलावा अब समुद्री जीवों से जुड़े नए आकर्षण भी विकसित किए जा रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि पनवेल में बनने वाला मेगा एक्वेरियम मुंबई महानगर क्षेत्र के पर्यटन मानचित्र को और मजबूत कर सकता है। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होने की संभावना है।

पेंगुइन की सफलता के बाद नया प्रयोग मुंबई के भायखला जू में हम्बोल्ट पेंगुइन आने के बाद पर्यटकों की संख्या में काफी बढ़ोतरी देखी गई थी। पेंगुइन देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जू पहुंचते हैं। अब सी लायन को नए एक्वेरियम में शामिल करने की योजना को भी इसी तरह के आकर्षण के रूप में देखा जा रहा है।

मुंबई: महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 28 अगस्त से लागू होगा, गजट जारी किया गया

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने बहुचर्चित 'महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम' को लागू करने की तारीख का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है।हाल ही में जारी आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, यह कानून 28 अगस्त, 2026 से पूरे राज्य में लागू हो जाएगा। 'महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक' का मकसद जबरदस्ती, धोखाधड़ी, दबाव, लालच या शादी के जरिए होने वाले धर्म परिवर्तन को रोकना है। साथ ही, गलत जानकारी देकर, अनुचित प्रभाव डालकर या प्रलोभन देकर कराए जाने वाले धर्म परिवर्तन पर भी रोक लगाना है।

17 मार्च को महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026' का मसौदा पेश किया, जिसमें जेल की सजा का प्रावधान है। विधानसभा में विधेयक का मसौदा पेश करते हुए महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा, ''हाल के वर्षों में एक धर्म से दूसरे धर्म में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के मामले सामने आए हैं। ये घटनाएं कानून-व्यवस्था को

बिगाड़ती हैं और सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाती हैं। मैं विधानसभा विधेयक संख्या 20, 2026 - 'महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026' पेश करता हूं।''

इससे पहले मार्च में, शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा में इस विधेयक - 'धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026' या 'महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक' - को अपनी पार्टी का समर्थन दिया था। इस विधेयक का मकसद राज्य में गैर-कानूनी धर्म परिवर्तन पर रोक लगाना है। पत्रकारों से बात करते हुए ठाकरे ने जोर देकर कहा कि हालांकि धर्म की आजादी एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उनकी पार्टी किसी व्यक्ति का धर्म बदलने के लिए जबरदस्ती, शोषण या धोखाधड़ी से लालच देने के सख़्त खिलाफ है। ''मैंने धर्म परिवर्तन से जुड़ा विधेयक देखा... अगर कोई धमकी देकर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए... हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं।'' मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ किया है कि यह विधेयक किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करने से नहीं रोकता, बल्कि जबरदस्ती और धोखाधड़ी से किए जाने वाले धर्म परिवर्तन को रोकता है।

संपादकीय...

डिजिटल भुगतान बढ़ा...

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

नकद लेनदेन के कई फायदे हैं। एक तो निपटान तुरंत हो जाता है और दूसरा लेनदेन की कोई लागत नहीं होती। इसके अलावा नकद लेनदेन गोपनीय भी बने रहते हैं। डिजिटल लेनदेन अपने पीछे एक निशान छोड़ते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उनका पता लगाया जा सकता है। ऐसी तमाम वजह हैं जिनके चलते लोग नकदी का उपयोग करना पसंद करते हैं भले ही डिजिटल लेनदेन के माध्यमों का उल्लेखनीय विस्तार हो गया हो। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) की असाधारण सफलता के कारण डिजिटल लेनदेन का तेज विस्तार सहज ही यह संकेत देता है कि अर्थव्यवस्था में नकदी का उपयोग घटा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू ने जकार्ता, इंडोनेशिया में दिए गए एक संबोधन में इस पहलू को उजागर किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान अपनाए जाने के बावजूद नकद का प्रचलन कम नहीं हुआ है। विशेष रूप से ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों, निम्न आय समूहों और छोटे व्यवसायों में इसका उपयोग हो रहा है।

बैंक नोट जारी करने का नियमन 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना के मुख्य कारणों में से एक था। केंद्रीय बैंक यह कार्य बैंकिंग प्रणाली और अन्य संस्थानों के सहयोग से करता रहा है। वर्तमान में लगभग संख्या के हिसाब से रुपये के 176 अरब नोट प्रचलन में हैं जो अमेरिकी डॉलर या यूरो नोटों की तुलना में कहीं अधिक हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि निम्न मूल्यवर्ग के नोटों की संख्या ज्यादा है। इससे प्रणाली में नए नोटों की बड़ी मात्रा में आपूर्ति और क्षतिग्रस्त नोटों को वापस लेना होता है। हर साल लगभग 28-30 अरब नए नोट छापे जाते हैं और लगभग 21 अरब नोट नष्ट कर दिए जाते हैं। यह हमेशा महत्त्वपूर्ण है कि नोट अच्छी गुणवत्ता के हों और उनमें आवश्यक सुरक्षा विशेषताएं मौजूद हों। मुद्रा प्रणाली को प्रभावी ढंग से चलाना मौद्रिक संप्रभुता बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। रिजर्व बैंक अब परीक्षण के आधार पर पॉलिमर नोट जारी करने की योजना बना रहा है। इससे नोट अधिक टिकाऊ होंगे और दीर्घकाल में यह किफायती होगा। जैसा कि मुर्मू ने उल्लेख किया प्रचलन में मुद्रा दो अंकों की दर से बढ़ रही है भले ही व्यक्तिगत लेनदेन में नकद का हिस्सा घट रहा है। इससे रिजर्व बैंक के लिए भविष्य की मांग का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है और उत्पादन व वितरण के लिहाज से जटिलताएं पैदा होती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में नकद की सतत मांग पर बहस होनी चाहिए।

editor@rokthoklekhani.com
+91 9987775650
Faisal Shaikh @faisalrokthok

मुंबईः जीएमएलआर में नई शुरूआत, पार्क के नीचे सुरंग खुदाई शुरू...

मुंबईः मुंबई के बहुप्रतीक्षित गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड प्रोजेक्ट ने विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। इस बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तहत संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे बनने वाली जुड़वां सुरंगों में से एक की खुदाई का काम शुरू हो गया है। टनल बोरिंग मशीन 'तुलसी' के सफल संचालन के साथ ही इस महत्वाकांक्षी परियोजना ने एक नए चरण में प्रवेश कर लिया है। मुंबई के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों को जोड़ने वाली इस परियोजना को शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। गोरेगांव ईस्ट को मुलुंड वेस्ट से जोड़ने वाली ये सुरंगें शहर के दो प्रमुख हिस्सों के बीच यात्रा के समय को कम करने में मदद करेंगी।

5.30 किलोमीटर लंबी होंगी जुड़वां सुरंगें गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड परियोजना के फेज-3(बी) के तहत बनाई जा रही इन जुड़वां सुरंगों की लंबाई करीब 5.30 किलोमीटर होगी। प्रत्येक सुरंग तीन लेन वाली होगी, जिससे बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही आसान हो सकेगी। यह सुरंग गोरेगांव ईस्ट स्थित दादासाहेब फाल्के चित्रनगरी क्षेत्र को मुलुंड वेस्ट के अमर नगर से जोड़ेगी। परियोजना पूरी होने के बाद यह मुंबई के लिए एक महत्वपूर्ण ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के रूप में काम करेगी।

वर्तमान समय में मुंबई के पश्चिमी और पूर्वी उपनगरों के बीच आवागमन के लिए लोगों को लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। खासकर पीक ऑवर में भारी ट्रैफिक के कारण यात्रियों को काफी समय सड़कों पर बिताना पड़ता है। जीएमएलआर परियोजना के पूरा होने से इस समस्या में काफी राहत मिलने की उम्मीद है। आधुनिक तकनीक से हो रही सुरंग की खुदाई संजय गांधी नेशनल पार्क जैसे संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्र के नीचे सुरंग निर्माण एक बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। इस चुनौती को देखते हुए परियोजना में आधुनिक टनलिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई का एक महत्वपूर्ण हरित क्षेत्र है, जहां बड़ी संख्या में वनस्पतियां और वन्यजीव पाए जाते हैं। ऐसे में इस क्षेत्र के नीचे सुरंग बनाना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। परियोजना तैयार करते समय पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक मशीनों और वैज्ञानिक तरीकों के माध्यम से निर्माण कार्य को इस तरह आगे बढ़ाया जा रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। सुरंग का निर्माण जमीन के काफी नीचे किया जा रहा है, जिससे पार्क के ऊपरी हिस्से और वहां मौजूद प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखा जा सके। मुंबई के ट्रैफिक को मिलेगी राहत मुंबई जैसे घनी आबादी वाले शहर में ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है। खासकर पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों के बीच यात्रा करने वाले लोगों को रोजाना जाम का सामना करना पड़ता है। गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड परियोजना के पूरा होने के बाद लोगों को एक वैकल्पिक तेज मार्ग उपलब्ध होगा। इससे यात्रा का समय कम होगा और मौजूदा सड़कों पर वाहनों का दबाव भी घटेगा। यह परियोजना केवल यातायात सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि मुंबई के भविष्य के विकास और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

महिला ने प्रेमी संग मिलकर लिव-इन पार्टनर की हत्या की

नासिकः महाराष्ट्र के नासिक शहर में एक दिल दहला देने वाली हत्या की घटना सामने आई है। यहां एक महिला ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर अपने ही लिव-इन पार्टनर की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि महिला और मृतक करीब 15 वर्षों से साथ रह रहे थे। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को कसारा घाट के घने जंगलों में फेंक दिया। मृतक की पहचान वसंत गोरखनाथ सतपुते (40) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर उसका गला रेतकर हत्या की और फिर शव को ठिकाने लगाने के लिए जंगल में फेंक दिया।

इस मामले में पुलिस ने महिला समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में हसीना शेख (45), साहिल रफीक शेख (23), मोइन मुख्तार शेख (24) और सरफराज अबरार सैयद (22) शामिल हैं। 5 अगस्त से लापता था वसंत सतपुते पुलिस के मुताबिक, नासिक शहर के इंदिरा नगर पुलिस स्टेशन में वसंत सतपुते के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में बताया गया था कि वह 5 अगस्त से गायब है। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को कई महत्वपूर्ण सुराग मिले, जिसके आधार पर लापता व्यक्ति की तलाश तेज की गई। जांच आगे बढ़ने पर पुलिस को हत्या की आशंका हुई और संदिग्धों से पूछताछ शुरू की गई। पूछताछ में कथित तौर पर हत्या की साजिश का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर कसारा घाट क्षेत्र के जंगल से शव बरामद किया। महिला ने प्रेमी और साथियों के साथ रची साजिश पुलिस जांच के अनुसार, हसीना शेख ने अपने प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। शुरूआती जांच में सामने आया है कि हत्या की योजना पहले से बनाई गई थी। आरोप है कि महिला ने अपने साथियों की मदद से वसंत सतपुते की हत्या की और बाद में शव को जंगल में ले जाकर फेंक दिया।

सांगली : कूड़े के विवाद में डबल मर्डर... खेला खूनी खेल पति-पत्नी की गई जान

सांगलीः डबल मर्डर की एक ऐसी चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने सांगली जिले को एक बार फिर हिलाकर रख दिया है। दरअसल, कुपवाड़ा में दरवाजे पर कचरा फेंकने की वजह से शुरू हुआ झगड़ा सीधे डबल मर्डर तक पहुंच गया है। इस मामले में पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी है और अब गंभीर रूप से घायल पति की भी इलाज के दौरान मौत हो गई है, जिससे पूरे जिले में खलबली मच गई है। पुलिस ने इस मामले के संदिग्ध आरोपी फरीद अब्दुल शेख को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब गुस्साए रिश्तेदार और नागरिक आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यह पूरा विवाद सांगली के कुपवाड़ इलाके में पड़ोसियों के बीच दरवाजे पर कचरा फेंकने को लेकर शुरू हुआ था। यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि फरीद अब्दुल शेख पर मनीषा मोहन केसरकर और उनके पति मोहन केसरकर पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। हमले में मनीषा केसरकर की मौत हो गई। वहीं, गंभीर रूप से घायल मोहन केसरकर का मिराज सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन मंगलवार को इलाज के दौरान मोहन केसरकर की भी मौत हो गई। इस वजह से कुपवाड़ा का यह मामला अब डबल मर्डर केस में बदल गया है, क्योंकि पति-पत्नी दोनों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मिराज सरकारी अस्पताल में रिश्तेदारों और नागरिकों की भारी भीड़ जमा हो गई। इस घटना से इलाके में गुस्से का माहौल है और रिश्तेदार मांग कर रहे हैं कि संदिग्ध आरोपियों पर बिना किसी देरी के फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए और मौत की सजा समेत सख्त से सख्त सजा दी जाए। बता दें कि यह घटना बीते शनिवार की है, जहां कुपवा ड़ा की श्याम नगर शांति कॉलोनी में रहने वाले 45 वर्षीय मोहन नागप्पा केसरेकर एवं उनकी 35 वर्षीय पत्नी मनीषा मोहन केसरेकर और बगल में रहने वाले, मूलरूप से वानलेसवाड़ी के रहने वाले फरीद अब्दुल शेख के बीच कूड़ा फेंकने को लेकर बहस हो गई।

एक व्यक्ति के नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन...?
लागू होगा नया नियम; अतिरिक्त नंबर होंगे बंद!

नई दिल्ली : दूरसंचार विभाग ने एक व्यक्ति के नाम पर मोबाइल कनेक्शनों की निर्धारित सीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिए नई निगरानी व्यवस्था शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत टेलीकॉम कंपनियां अधिकतम सीमा तक नंबर रखने वाले ग्राहकों की तस्वीरों के आधार पर पहचान कर सकेंगी। 24 अगस्त से नया कनेक्शन लेने वाले ऐसे ग्राहकों को रोका जा सकेगा।

मोबाइल कनेक्शन को लेकर सरकार ने नियमों के पालन को और सख्त करने की तैयारी कर ली है। दूरसंचार विभाग ने ऐसे ग्राहकों की पहचान और निगरानी के लिए नए निर्देश जारी किए हैं, जिनके नाम पर पहले से तय सीमा तक मोबाइल कनेक्शन हैं। 24 अगस्त 2026 से टेलीकॉम कंपनियां फोटो के जरिए ऐसे ग्राहकों की पहचान कर सकेंगी और तय सीमा से अधिक नया मोबाइल कनेक्शन लेने से उन्हें रोकेंगी। दूरसंचार विभाग ने 17 अगस्त को जारी सर्कुलर में कहा कि एक व्यक्ति के नाम पर सभी टेलीकॉम कंपनियों और सभी लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों में अधिकतम नौ मोबाइल कनेक्शन हो सकते हैं। जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर के लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों में यह सीमा छह मोबाइल कनेक्शन की है।

तय सीमा से ज्यादा सिम होंगे बंद

विभाग ने कहा कि किसी ग्राहक के नाम पर तय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन पाए जाने पर अतिरिक्त नंबरों को बंद कराने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके लिए पहले से डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिए अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियों और सेवा क्षेत्रों में एक व्यक्ति के नाम पर चल रहे मोबाइल कनेक्शनों की पहचान और ग्रुपिंग की व्यवस्था है।

नए निदेशों के तहत 23 अगस्त 2026 से डीआइपी पर उन ग्राहकों की फोटो की प्रतिनिधि इमेज उपलब्ध कराई जाएगी, जिनके नाम पर मोबाइल कनेक्शन की निर्धारित अधिकतम सीमा पूरी हो चुकी है। सभी टेलीकॉम कंपनियों को इन तस्वीरों को रोजाना डाउनलोड करना होगा। इसके बाद 24 अगस्त से टेलीकॉम कंपनियों को तकनीकी और संगठनात्मक उपायों के जरिए ऐसे ग्राहकों की पहचान करनी होगी, जो तय सीमा पार करके नया मोबाइल कनेक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। पहचान होने पर ग्राहक को बताया जाएगा कि उसके नाम पर पहले ही अधिकतम मोबाइल कनेक्शन हैं और उसे नया कनेक्शन नहीं दिया जा सकता।

दूरसंचार विभाग ने कहा है कि शुरूआत में टेलीकॉम कंपनियां इस व्यवस्था को डी+1 यानी ग्राहक के नाम पर नया कनेक्शन दर्ज होने के अगले दिन जांच के आधार पर लागू कर सकती हैं। बाद में इसे मोबाइल कनेक्शन के पंजीकरण और सक्रिय करने की प्रक्रिया में रियल टाइम आधार पर शामिल करना होगा। यह व्यवस्था सभी टेलीकॉम कंपनियों को 30 नवंबर 2026 तक अपनी नामांकन और कनेक्शन सक्रिय करने की प्रक्रिया में पूरी तरह एकीकृत करनी होगी।

नई दिल्ली : इस्तीफे के बाद सरकार के खिलाफ हुए शहजाद पूनावाला?

नई दिल्ली : बीजेपी के तेज-तर्रार प्रवक्ता के तौर पर लंबे समय तक पार्टी की नीतियों का बचाव करने वाले शहजाद पूनावाला ने इस्तीफा देने के बाद अब ऐसा मुद्दा उठाया है, जो सीधे देश के मिडिल क्लास से जुड़ा है। बीजेपी छोड़ने के कुछ ही घंटे बाद पूनावाला ने सरकारों की टैक्स नीति और बदले में मिलने वाली सुविधाओं पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि भारत का मिडिल क्लास आज एटीएम बन चुका है और उससे लगातार अलग-अलग तरह के टैक्स वसूले जा रहे हैं। शहजाद पूनावाला ने अपने एक्स अकाउंट पर वीडियो पोस्ट कर सवाल किया कि क्या भारत का मिडिल क्लास जितना टैक्स देता है, उसी अनुपात में उसे सुविधाएं भी मिलती हैं? उन्होंने कहा

कि जब तक देश के नागरिकों को वर्ल्ड-क्लास सुविधाएं नहीं मिलतीं, तब तक नौकरीपेशा मिडिल क्लास के लिए पर्सनल इनकम टैक्स खत्म करने का समय आ गया है।

पूनावाला ने 17 अगस्त 2026 को बीजेपी से इस्तीफा दिया था। इस्तीफे की चिट्ठी भी उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर साझा की। लेकिन पार्टी छोड़ने से पहले ही उन्होंने मिडिल क्लास के मुद्दे पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। उन्होंने देश की बुनियादी सुविधाओं से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था तक पर सरकारों से जवाब मांगा।

पूनावाला ने हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब किसी परिवार को अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलानी होती है तो उसे अक्सर प्राइवेट स्कूल का रुख करना पड़ता है। वहीं, माता-पिता के इलाज के लिए भी प्राइवेट अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता है। उनका सवाल है कि अगर टैक्सपेयर्स लगातार सरकार को भुगतान कर रहे हैं तो उन्हें बेहतर सरकारी स्कूल और बेहतर सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों नहीं मिलनी चाहिए?

केरल में दो नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स का मुख्य न्यायाधीश ने किया उद्घाटन; लापता बच्चों के बायोमेट्रिक जांच की मांग

नई दिल्ली : भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि केरल के इरिंजालाकुडा और चावक्काड में बने दो नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स न्याय की बढ़ती जरूरतों से निपटने और अदालतों को आम लोगों के करीब लाने की दिशा में महत्वपूर्ण निवेश हैं। केरल सरकार ने करीब 100 करोड़ रुपये की लागत से इन परिसरों का निर्माण कराया है, जिनका मंगलवार शाम मुख्य न्यायाधीश ने वर्चुअल उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि जिले में करीब 30 हजार सिविल मामले और एक लाख से अधिक आपराधिक मामले लंबित हैं।

बढ़ती और जटिल होती सामाजिक व्यवस्था के साथ अदालतों पर भी दबाव बढ़ रहा है, ऐसे में नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स न्याय व्यवस्था की क्षमता मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इन परिसरों की खासियत सिर्फ नई इमारतें जुड़ना नहीं है, बल्कि छोटे शहरों और कस्बों में रहने वाले लोगों के लिए न्याय को अधिक सुलभ बनाना है। परिसरों में मेडिएशन हॉल की व्यवस्था संस्थागत रूप से मध्यस्थता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दिखाती है, ताकि हर विवाद को लंबी सुनवाई से गुजरना जरूरी न हो। फैमिली कोर्ट में अलग-अलग क्यूबिकल वाले काउंसलिंग रूम लोगों को निजी और सम्मानजनक माहौल उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने महिला वकीलों के लिए अलग हॉल बनाए जाने की भी सराहना की और कहा कि न्याय व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है, इसलिए उन्हें सम्मानजनक और समान पेशेवर माहौल मिलना चाहिए। उनके मुताबिक आधुनिक न्यायिक संस्थान को लोगों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील होने के साथ संवाद, समझौते और गरिमा के लिए भी पर्याप्त जगह देनी चाहिए।

पुक्कलम का उदाहरण देकर समावेशी न्याय व्यवस्था का संदेश

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने केरल के ओणम पर्व के दौरान बनाए जाने वाले पारंपरिक फूलों के कालीन ''पुक्कलम'' का उदाहरण देते हुए कहा कि न्याय व्यवस्था भी उतनी ही समावेशी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अलग-अलग रंग, आकार और प्रकार के फूल मिलकर पुक्कलम को सुंदर बनाते हैं और उसी तरह न्याय व्यवस्था में शहरों, ग्रामीण इलाकों और दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए जगह होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को यह महसूस होना चाहिए कि न्याय व्यवस्था उसकी अपनी है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य के कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति के कारण समारोह में व्यक्तिगत रूप से शामिल न हो पाने पर खेद जताया और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी सुरक्षा, मजबूती और जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

गाजियाबाद: चाइनीज मांझे से कटी डिलीवरी बॉय की गर्दन... अस्पताल में मौत!

गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मेरठ-दिल्ली हाइवे पर शनिवार को एक दिन दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक डिलीवरी बॉय की मौत हो गयी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतक युवक रवि राज मूल रूप से बिहार के खगड़िया जिला का रहने वाला और नोएडा में सेक्टर 63 के बहरामपुर में गली नंबर 11 में रह रहा था. वह अपने दोस्त नरेश के साथ जा रहा था तभी तेज बाइक पर मांझा उसकी गर्दन में लिपट गया और खून की धार छूट पड़ी, जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

क्या था पूरा घटना क्रम ?

एसीपी इंदिरापुरम ने बताया की 15 अगस्त को मृतक रवि राज उम्र 25 साल पुत्र पवन कुमार हाल निवासी गली नंबर 11 बहरामपुर थाना सेक्टर 63 नोएडा, मूल पता- ग्राम गोपालपुर जिला खंगड़िया बिहार का रहने वाला था. रवि ऑनलाइन डिलीवरी का काम करता था. रवि अपने दोस्त नरेश पुत्र मैकासी निवासी गली नंबर 14 बहरामपुर थाना सेक्टर 63 नोएडा, मूल पता- ग्राम खादराबाद जिला संभल के साथ खोड़ा होते हुए मेरठ-दिल्ली हाईवे से बाइक से सवार होकर गाजीपुर की तरफ जा रहे थे.

बाइक मृतक रवि राज चला रहा था और नरेश बाइक पर रविराज के पीछे बैठा हुआ था. जब यह दोनों मीडिया हाउसके पास पहुंचे तो पुलिस को नरेश के बताये अनुसार रविराज के गले में पतंग का मांझा आकर टकराया. जिससे रविराज की गर्दन मांझा काटता चला गया. बाइक तेजी में होने के कारण लड़खड़ा गई कि तभी नरेश ने पीछे से बाइक का हैंडल पकडकर कंट्रोल करते हुए साइड में लगाई. लेकिन तब तक रविराज की गर्दन कट चुकी थी.

छह साल बाद ट्रंप का बड़ा दावा

"2020 के चुनाव में 24 हजार गैर-नागरिकों ने डाला था वोट"

वॉशिंगटन : भारत की चुनाव प्रक्रिया की प्रशंसा करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि 2020 के अमेरिकी चुनाव में 24 हजार से अधिक गैर-नागरिकों ने अवैध रूप से मतदान किया था। उन्होंने अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के हवाले से यह दावा किया है। ब्यूरो इस समय 2020 के मतदाता रिकार्ड की समीक्षा कर रहा है। ट्रंप ने मंगलवार को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि जनगणना ब्यूरो मतदाता रिकार्ड को उनके नागरिकता रिकार्ड से मिलाकर जांच कर रहा है।

ट्रंप के दावे में क्या-क्या?

ट्रंप ने आगे कहा कि पहले 12.8 करोड़ मतदाताओं की जांच में जनगणना ब्यूरो ने साबित किया है कि 24 हजार से ज्यादा गैर-नागरिकों ने अवैध रूप से मतदान किया किया था। उन्होंने कहा कि जनगणना ब्यूरो अब अगले 3.2 करोड़ मतदाताओं का विश्लेषण करने जा रहा है और यह संख्या बहुत ज्यादा बढ़ेगी।

ट्रंप ने 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपने दावे को दोहराते हुए कहा, ''मैंने चुनाव जीता था।'' इसके साथ ही ''सेव अमेरिका एक्ट'' को पारित की अपील करते हुए ट्रंप ने कहा, ''हमें सेव अमेरिका एक्ट को पारित करना चाहिए। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।

ट्रंप के इस टिप्पणी के मायने क्या?

बता दें कि ट्रंप की यह टिप्पणी ''सेफगार्ड अमेरिकी वोटर एलिजिबिलिटी (सेव) अमेरिका एक्ट के संदर्भ में आई है। उन्होंने अमेरिका में मतदान प्रक्रिया में बड़े बदलाव से जुड़े इस विधेयक का समर्थन किया है, जिसे 29 जनवरी को अमेरिकी संसद में पेश किया गया था।

भारत की चुनाव प्रक्रिया की तारीफ की थी

अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक दिन पहले ही न सिर्फ भारतीय चुनाव प्रक्रिया की तारीफ की थी, बल्कि भारत जैसी चुनाव प्रक्रिया को अमेरिका में भी अपनाए जाने की वकालत की थी। भारत के मतदाता पहचान पत्र का हवाला देते हुए ट्रंप ने कहा कि अब ''सेव अमेरिका एक्ट'' को पारित करने का समय आ गया है।

चीन का नया फरमान, चेंगदू के स्कूलों से लेकर अस्पतालों तक धार्मिक आस्था की जांच हुई सख्त

बीजिंग। चीन के सिचुआन प्रांत के चेंगदू शहर में सरकार ने सार्वजनिक कार्यस्थलों और स्कूलों में लोगों की धार्मिक आस्था की जांच का दायरा बढ़ा दिया है। अस्पताल के कर्मचारियों और छात्रों-परिवारों से धार्मिक विश्वासों की जानकारी मांगी जा रही है। द एपोक टाइम्स की 14 अगस्त की रिपोर्ट के अनुसार, लीक हुए आंतरिक दस्तावेजों और नाम न बताने की शर्त पर बात करने वाले लोगों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है।

चेंगदू के एक सार्वजनिक अस्पताल में जारी आंतरिक नोटिस में कहा गया कि वैचारिक, जातीय और धार्मिक कार्य की नियमित जांच के तहत सभी कर्मचारियों (स्थायी, अनुबंधित और अस्थायी) की धार्मिक

आस्था का व्यापक सर्वेक्षण किया जा रहा है। कर्मचारियों को अपनी धार्मिक संबद्धता की जानकारी देनी होगी और कोई भी विवरण छिपाने या छोड़ने की अनुमति नहीं है। जिनकी कोई धार्मिक आस्था नहीं है, उन्हें भी ''कोई धार्मिक विश्वास नहीं'' के रूप में पंजीकरण कराना होगा।

नोटिस में कहा गया कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) के सदस्य धर्म का पालन नहीं कर सकते। धार्मिक आस्था रखने वाले कर्मचारियों को अपनी पार्टी शाखा को इसकी रिपोर्ट करनी होगी। कार्यस्थल पर धार्मिक गतिविधियां और धर्म प्रचार भी प्रतिबंधित हैं।

सिचुआन के एक विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कर्मचारी ने बताया कि स्कूल छात्रों के परिवार के सदस्यों की धार्मिक संबद्धता की भी जांच कर रहे हैं और जानकारी उच्च अधिकारियों को सौंप रहे हैं। चेंगदू शिक्षा अधिकारियों के एक कर्मचारी ने कहा कि नए छात्र स्कूल में प्रवेश से पहले हर साल परिवार की पृष्ठभूमि जांच होती है, जिसमें धार्मिक आस्था की जानकारी भी शामिल होती है।

ये कदम सीसीपी की व्यापक नीति का हिस्सा बताए जाते हैं, जिसमें धार्मिक मामलों को राजनीतिक और वैचारिक प्रबंधन का मुद्दा माना जाता है। चीन सरकार धर्म के चीनीकरण की नीति को बढ़ावा दे रही है, जिसके तहत धार्मिक समूहों को चीनी कानून और राज्य की प्राथमिकताओं के अनुरूप चलना होता है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने धार्मिक मामलों पर पार्टी के नेतृत्व को और मजबूत करने पर जोर दिया है।

डियर ट्रंप पाकिस्तान पर एक्शन लीजिए,

बलूच नेता ने अमेरिकी राष्ट्रपति को लिखा लेटर

वाशिंगटन। बलूच अमेरिकन कांग्रेस के अध्यक्ष तारा चंद ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को पत्र लिखकर बलूचिस्तान के सुराब जिले में हाल ही में हुए पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। इसमें रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं और बच्चों समेत 30 से अधिक नागरिकों की मौत हो गई।

अपने पत्र में तारा चंद ने ट्रंप को लिखा, ''हम आपके प्रशासन से विनम्रता से अनुरोध करते हैं कि इन गंभीर आरोपों की जांच की जाए और यह निर्धारित किया जाए कि क्या किसी अमेरिकी मूल के विमान, हथियार, ड्रोन, प्रौद्योगिकी, घटक या अन्य सैन्य उपकरणों का उपयोग इस रिपोर्ट किए गए ऑपरेशन में किया गया था।''

बलूच समुदाय की ओर से उन्होंने अमेरिकी प्रशासन से सुराब में रिपोर्ट किए गए हवाई हमलों और नागरिक हताहतों की जांच करने, यह निर्धारित करने का आग्रह किया कि क्या अमेरिकी मूल के सैन्य उपकरण या प्रौद्योगिकी शामिल थी और पाकिस्तान को आपूर्ति किए गए संबंधित अमेरिकी रक्षा उपकरणों की उचित अंत-उपयोग और अनुपालन समीक्षा करने का अनुरोध किया।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर क्यों कमजोर हो रही ईरान की पकड़?

तेहरान। अमेरिका और ईरान के बीच बीते पांच महीनों से ज्यादा समय से जारी संघर्ष विफल शांति वार्ता और नाक की लड़ाई की भेंट चढ़ता आया है। दूसरी तरफ इस बात में भी कोई दोहराई नहीं है कि इस संघर्ष का सबसे ज्यादा असर दुनिया के सबसे संवेदनशील और अहम जलमार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर देखने को मिला है।

हालांकि बात यहीं खत्म नहीं होती, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच अब इस रास्ते से जुड़े व्यापार और सुरक्षा को लेकर भी बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में अब सवाल होर्मुज पर ईरान की पकड़ को लेकर खड़े हो रहे हैं।

होर्मुज पर ईरान की पकड़ कैसे हम हुई?

इस बात को ऐसे समझिए कि बीते कुछ दिनों से होर्मुज पर अमेरिकी नौसेना की सख्त नाकेबंदी, समुद्री बारूदी सुरंगों के सफाए और अमेरिकी सुरक्षा के भरोसे जहाजों द्वारा ''ओमान रूट'' व ''डार्क शिपिंग'' जैसे वैकल्पिक रास्तों के इस्तेमाल से ईरान का दबदबा इस जलमार्ग पर तेजी से घट रहा है। इतना ही नहीं ईरान की टोल टैक्स वसूलने की जिद और हमलों के बावजूद, अंतरराष्ट्रीय व्यापार अब उसकी पकड़ से बाहर होता दिख रहा है, जो वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए एक बड़ा बदलाव है।

ट्रंप के दांवों के मायने समझिए

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि इस जलमार्ग से सभी समुद्री बारूदी सुरंगे हटा दी गई हैं या उन्हें नष्ट कर दिया गया है।ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ फिलहाल कोई बातचीत

नहीं हो रही है और अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी अभी भी पूरी सख्ती से जारी है।

ओमान वाले नए रास्ते का इस्तेमाल

गौर करने वाली बात यह है कि पारंपरिक रूप से इस रास्ते पर ईरान का दबदबा माना जाता था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। मैरीटाइम डेटा के मुताबिक, पिछले दो हफ्तों में इस रास्ते से गुजरने वाले अधिकांश जहाजों ने ''ओमान रूट'' का इस्तेमाल किया है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा अधिकृत एक शिपिंग चैनल है, जिसका ईरान कड़ा विरोध करता है।

ईरान की धमकियों और हमलों के जोखिम के बावजूद, जहाज अमेरिकी सुरक्षा के भरोसे इस रास्ते से गुजर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान अब इस जलमार्ग पर अपनी पकड़ आंशिक रूप से खो चुका है।

टोल टैक्स से ईरान को कैसे लगा झटका?

इस बात को ऐसे समझिए कि अमेरिका और ईरान के बीच हुआ समझौता खत्म होने के बाद ईरान की मंशा जहाजों से भारी टोल टैक्स वसूलने की थी। लेकिन ओमान रूट के इस्तेमाल से जहाजों को ईरान के नियंत्रण वाले क्षेत्र से नहीं गुजरना पड़ रहा है, जिससे ईरान को किसी भी तरह का ट्रांजिट फीस या टैक्स नहीं मिल पा रहा है। खाड़ी देशों के लोग भी ईरान को टैक्स देना पसंद नहीं कर रहे हैं।

''डार्क शिपिंग'' और तेल का व्यापार

सऊदी अरब, कुवैत और यूएई जैसे खाड़ी देशों ने अपने बड़े तेल टैंकरों को इस रास्ते से भेजना शुरू कर दिया है। ईरान के हमलों से बचने के लिए ये जहाज कई हफ्तों तक अपने ट्रांसपॉडर (लोकेशन बताने वाला यंत्र) बंद रखकर सफर कर रहे हैं, जिसे ''डार्क शिपिंग'' कहा जाता है।

अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट के अनुसार, वर्तमान में इस रास्ते से तेल का परिवहन युद्ध से पहले के औसत (करीब 2 करोड़ बैरल प्रतिदिन) के काफी करीब यानी लगभग 1.5 करोड़ बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया है।

अंतरराष्ट्रीय जहाजों ने छोड़ दी ईरान की परवाह

साफ शब्दों में कहा जाए तो अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी और सुरक्षा के भरोसे अंतरराष्ट्रीय जहाजों ने ईरान के नियमों और टोल टैक्स की परवाह करना छोड़ दिया है। ऐसे में वैकल्पिक रास्तों (ओमान रूट) और छिपे हुए यातायात (डार्क शिपिंग) के बढ़ने से वैश्विक ऊर्जा का यह सबसे बड़ा रास्ता अब ईरान के हाथों से फिसलता हुआ नजर आ रहा है।

अक्षय ओबेरॉय अभिनीत ‘लव लॉटरी’ का टीजर आउट

मुंबईः बहुप्रतीक्षित क्राइम-सस्पेंस सोशल ड्रामा ‘लव लॉटरी’ का टीज़र रिलीज हो गया है। अक्षय ओबेराय, हेली दारूवाला स्टाररर फ़िल्म लव लॉटरी के टीज़र में रिश्तों, शादी, कानूनी लड़ाइयों, एलिमनी और महिलाओं के पक्ष में बनाए गए कानूनों के कथित दुरुपयोग जैसे संवेदनशील मुद्दों की झलक है। साथ ही, फिल्म पुरुष अधिकारों और उन परिस्थितियों पर भी ध्यान खींचती है, जिनके बारे में अक्सर खुलकर बात नहीं की जाती।

टीजर की शुरुआत से ही फिल्म प्यार, शादी और भरोसे से जुड़े ऐसे पहलुओं की झलक देती है, जहां भावनाएं धीरे-धीरे कानूनी और आर्थिक विवादों में उलझती नजर आती हैं। फिल्म का शीर्षक ‘लव लॉटरी’ भी इसी ओर इशारा करता है कि कुछ रिश्ते प्यार और विश्वास की खूबसूरत शुरुआत के बजाय ऐसी परिस्थितियों में बदल जाते हैं, जहां जिंदगी किसी ‘लॉटरी’ से कम नहीं लगती।

38 सेकंड के इस टीज़र में अक्षय ओबेरॉय, हेली दारूवाला और फिल्म के अन्य कलाकार दमदार और भावनात्मक परिस्थितियों में नजर आते हैं। अक्षय ओबेरॉय का किरदार कई सवालों और उलझनों के बीच फंसा दिखाई देता है, वहीं दूसरे किरदारों की रहस्यमयी एंट्री कहानी में सस्पेंस को और गहरा करती है।

टीज़र की सबसे खास बात उसका क्लाइमैक्स है, जहां कोर्टरूम में बजता हथौड़ा, अचानक सुनाई देती गोली की आवाज और कई अनसुलझे सवाल दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा देते हैं। आखिरी पलों में पुरुष अधिकारों का मुद्दा भी प्रमुखता से सामने आता है और यह सवाल छोड़ जाता है कि आखिर अदालत तक पहुंची इस कहानी के पीछे की असली सच्चाई क्या है?

अभिनेता अक्षय ओबेरॉय कहते हैं, “यह फिल्म उन मुद्दों पर बात करती है, जिनके बारे में हमारे समाज में अधिकतर पुरुष खुलकर बात करने में हिचकिचाते हैं या शर्म महसूस करते हैं। कुछ कानूनों के कथित दुरुपयोग की वजह से समाज के एक वर्ग ने लंबे समय तक दर्द झेला है। हमारी कोशिश है कि ऐसे लोगों की आवाज सामने आए। और यह भी समझना जरूरी है कि ऐसी परिस्थितियों का असर सिर्फ पुरुष पर ही नहीं पड़ता, बल्कि उसकी मां, बहन या उसके करीब रहने वाली कोई भी महिला इससे प्रभावित हो सकती है।”

साजन अग्रवाल की “लेडी बॉन्ड007” में सीमा पाहवा का वर्टिकल डेब्यू

मुंबई : दिग्गज अभिनेत्री सीमा पाहवा आगामी महिला-केंद्रित क्राइम थ्रिलर ‘लेडी बॉन्ड007’ के साथ वर्टिकल फॉर्मेट में अपना डेब्यू करने जा रही हैं। साजन अग्रवाल के निर्देशन में बनी इस सीरीज़ में सीमा पाहवा एक बिल्कुल अलग और अनदेखे अवतार में नजर आएंगी। वह मीनाक्षी बत्रा नाम की तेज-तर्रार और निडर जासूस का किरदार निभा रही हैं।

यह सीरीज़ क्रांति शनभाग के रॉकेट रील्स ओटीटी पर प्रीमियर होगी। कहानी मीनाक्षी बत्रा के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक रहस्यमयी मामले की जांच के लिए माइक फार्मा में हाउसकीपर बनकर अंडरकवर जाती हैं। मामला संदीप गुप्ता और उसकी कथित रूप से मृत बेटी अन्नू से जुड़ा है। न्याय की तलाश में शुरू हुई मीनाक्षी की जांच जल्द ही लालच, संपत्ति, हत्या और बदले की एक खतरनाक साजिश में बदल जाती है। वर्टिकल डेब्यू पर सीमा पाहवा ने कहा

“मैंने हमेशा ऐसे किरदारों को निभाना पसंद किया है, जो एक अभिनेत्री के तौर पर मुझे कुछ अलग करने का मौका दें।

बोल्ड सीन का कड़वा सच!

मुंबई : ओटीटी पर बोल्ड सीन्स देखकर दर्शकों को भले ही सबकुछ आसान लगे, लेकिन इन्हें शूट करना उतना ग्लैमरस नहीं होता। ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ फेम नेहल वडोलिया ने हाल ही में इंटीमेट सीन्स की शूटिंग को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। नेहल ने बताया कि ऐसे सीन्स में एक्ट्रेस का कंफर्ट सबसे जरूरी होता है। उनके मुताबिक, बोल्ड सीन शूट करने के बाद शरीर पर निशान पड़ जाते है और लिप्स में सूजन भी आ जाती है। इसलिए वह ऐसे सीन्स से पहले अपने डायलॉग वाले हिस्से शूट करना पसंद करती हैं। नेहल ने यह भी कहा कि ये सीन किसी मजे के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह डायरेक्शन के मुताबिक शूट किए जाते हैं और कोशिश रहती है कि इन्हें कम से कम टेक में पूरा किया जाए। दिलचस्प बात यह है कि नेहल ने अब बोल्ड इंडस्ट्री से दूरी बना ली है। उन्होंने बताया कि करीब साढ़े चार साल पहले उन्होंने यह काम छोड़ दिया और अब सोशल मीडिया के जरिए कमाई करती हैं।

काजल-आम्रपाली की तकरार में फिर लगी ‘मिर्ची’!

मुंबई : भोजपुरी मनोरंजन जगत का चर्चित शो ‘भोजपुरी बवाल’ शुरुआत से ही विवादों में है। काजल राघवानी और आम्रपाली दुबे के बीच चल रही तकरार ने अब नया मोड़ ले लिया है। शो के पहले एपिसोड में काजल ने दावा किया था कि एक प्रोड्यूसर ने उन्हें बताया था कि दिनेश लाल यादव के कहने पर उन्हें एक गाने से हटाकर आम्रपाली को मौका दिया गया था। अब शो में उसी प्रोड्यूसर प्रेम राय को बुलाया गया। दिनेश लाल यादव ने सीधे सवाल किया कि आखिर वह कौन-सा गाना था, जिसमें काजल को हटाने की बात कही गई थी। प्रेम राय ने साफ इनकार करते हुए कहा कि यह बात सरासर झूठ है और अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो इसे साबित किया जाए। इस पर आम्रपाली ने तंज कसते हुए कहा कि आखिर हर बार बाकी सभी गलत वैसे हो जाते हैं और काजल अकेली सही? वहीं काजल ने भी पलटवार करते हुए इशारा किया कि फिल्मी रिश्तों की वजह से अब सच बदल गया है। दोनों की नोकझोंक ने शो का माहौल और भी गरमा दिया है।

मुंबईः मीरा-भाईंदर से वसई-विरार मेट्रो कॉरिडोर को मिली मंजूरी, 5 साल में प्रोजेक्ट होगा पूरा

मुंबई : मुंबई के बाहर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने एमएमआर में मेट्रो कॉरिडोर के विस्तार को मंजूरी प्रदान कर दी है। सरकारी मंजूरी के बाद मीरा भाईंदर को वसई विरार को मेट्रो से कनेक्ट करने का रास्ता साफ हो गया है। 17,725 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस कॉरिडोर से मीरा रोड, वसई, नालासोपारा, नायगांव और विरार के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला हुआ है।

25 किमी लंबा होगा कॉरिडोर

मेट्रो-13 की कुल लंबाई 25.03 किमी होगी। इसमें 21.78 किमी एलिवेटेड और 3.25 किमी भूमिगत मार्ग होगा। कॉरिडोर पर कुल 16 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें 13 एलिवेटेड और तीन भूमिगत स्टेशन होंगे। एमएमआरडीए इस प्रोजेक्ट को लागू करेगा और मंजूरी के बाद इसे पांच साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

लोकल ट्रेन से होगी कनेक्ट

अधिक से अधिक यात्रियों को मेट्रो लाइन का लाभ पहुंचाने के लिए मेट्रो-13 को नायगांव, नालासोपारा, विरार रेलवे स्टेशन से जोड़ा जाएगा। साथ ही इस लाइन को दहिसर (पूर्व) से मीरा भाईंदर के बीच बने मेट्रो-9 से भी जोड़ा जायगा। मेट्रो-9 के नेताजी सुभाषचंद्र बोस स्टेडियम स्टेशन पर यह दोनों लाइन कनेक्ट होगी। मेट्रो 9 के जरिये लोग विरार से मुंबई तक मेट्रो में सफर कर सकेंगे। यात्रियों को मेट्रो के रूप में नया विकल्प उपलब्ध होगा। इस प्रोजेक्ट की खासियत वसई खाड़ी पर पांजू बेट को जोड़ने वाला 4.92 किमी लंबा छह लेन का संयुक्त सड़क-मेट्रो पुल होगा। चिखल डोंगरी में मेट्रो डिपो प्रस्तावित है। सभी मेट्रो स्टेशनों तक बस सेवा उपलब्ध कराने की भी योजना है।

सरकार के अनुसार वर्ष 2031 में इस कॉरिडोर से रोजाना करीब 4.49 लाख यात्री सफर कर सकते हैं। मेट्रो शुरू होने से सड़क मार्ग की तुलना में यात्रा का समय करीब 50 फीसदी तक कम होने की उम्मीद है। इससे निजी वाहनों और प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात का दबाव घटने के साथ कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी।

तस्वीरों के जरिए दिखे ठाणे के विकास की नई तस्वीर : डीसीएम शिंदे

मुंबईः एक तस्वीर सिर्फ. एक पल की कहानी नहीं होती, बल्कि उस एक फोटो के जरिए हजारों शब्द कहे जाते हैं। तस्वीर देखने के बाद, लोगों को उस घटना या हालात का एहसास होता है। साथ ही, तस्वीरों के जरिए पुरानी यादें भी ताजा हो जाती हैं। ठाणे बदल रहा है.. राज्य के उप मुख्य मंत्री एकनाथ शिंदे ने आज ठाणे में कहा कि फोटोग्राफरों को ठाणे के विकास को तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहिए, फोटोग्राफर को अपनी 'तीसरी आँख' लगातार खुली रखनी होगी।

वे वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के मौके पर ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ठाणे शहर दैनिक पत्रकार संघ की तरफ से मनपा भवन में आयोजित एक फोटोग्राफी नुमाइश के उद्घाटन पर बोल रहे थे। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन उप मुख्य मंत्री एकनाथ शिंदे ने किया। कार्यक्रम में सांसद नरेश म्हस्के, महापौर शर्मिला पिंपोलकर, सदन के नेता हनमंत जगदाले, विपक्ष के नेता अशरफ शानू पठान, अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे, तथा, ठाणे शहर दैनिक पत्रकार संघ के दिलीप शिंदे सहित पत्रकार संघ के पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य और बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद थे। एक फोटोग्राफर शब्दों से परे अपनी बात कह देता है।

मुंबईः पांच राज्यों में बैन हुआ एनालॉग पनीर सेहत के लिए कितना खतरनाक

मुंबईः देश के कई राज्यों में एनालॉग पनीर को लेकर सख्ती शुरू हो गई है। महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों ने इसके उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला किया है। सरकारों का कहना है कि बाजार में कई जगह ऐसे उत्पाद पनीर के नाम पर बेचे जा रहे हैं, जो असली दूध से बने पनीर नहीं हैं।इतिहास क्या होता है एनालॉग पनीर? एनालॉग पनीर ऐसा उत्पाद है जो देखने और स्वाद में असली पनीर जैसा बनाया जाता है, लेकिन इसे पूरी तरह या आंशिक रूप से दूध से नहीं बनाया जाता। इसमें दूध की जगह या दूध के साथ वनस्पति तेल, वेजिटेबल फैट, स्टार्च, इमल्सीफायर और अन्य खाद्य सामग्री का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे बनाने का मकसद कम लागत में पनीर जैसा उत्पाद तैयार करना होता है। यही कारण है कि यह होटल, रेस्टोरेंट और बड़े पैमाने पर खाद्य कारोबार में सस्ते विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। असली पनीर और एनालॉग पनीर में अंतर असली पनीरः दूध से तैयार किया जाता है इसमें दूध के प्रोटीन और पोषक तत्व होते हैं स्वाद और बनावट प्राकृतिक होती है एनालॉग पनीरः दूध के बजाय अन्य फैट और सामग्री का इस्तेमाल हो सकता है इसमें प्रोटीन की मात्रा कम हो सकती है, यह सस्ता विकल्प होता है कई बार इसे बिना सही जानकारी के पनीर बताकर बेचा जाता है सरकारों ने क्यों लगाया बैन? राज्य सरकारों का कहना है कि उपभोक्ताओं को असली पनीर के नाम पर ऐसा उत्पाद नहीं मिलना चाहिए,

मुंबईः एसआईआर विवाद पर अबू आजमी का हमला

मुंबईः महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, उन्हें दोबारा बहाल किया जाना चाहिए। ठाणे में मीडिया से बातचीत के दौरान अबू आजमी ने कहा कि एसआईआर के नाम पर किसी भी तरह की ऐसी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, जिससे किसी भी नागरिक के अधिकार प्रभावित हों। उन्होंने कहा कि यदि किसी बहाने से एनआरसी जैसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है तो उसका भी विरोध किया जाएगा।

हटाए गए नामों को बहाल करने की मांग

अबू आजमी ने कहा कि मतदाता सूची से हटाए गए लोगों के नाम वापस जोड़े जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर योग्य नागरिक को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए और किसी भी प्रक्रिया के कारण लोगों को इससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लोगों में चिंता का माहौल है और सरकार को इस मामले में पारदर्शिता बरतनी चाहिए।

एनआरसी को लेकर भी जताई चिंता

समाजवादी पार्टी नेता ने कहा कि किसी भी प्रक्रिया का इस्तेमाल नागरिकों को परेशान करने या उनके अधिकारों को कमजोर करने के लिए नहीं होना चाहिए। उन्होंने एनआरसी का जिक्र करते हुए कहा कि किसी भी बहाने से ऐसी व्यवस्था लागू करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की एकता और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत रखना सभी की जिम्मेदारी है। मुस्लिम समुदाय को लेकर दिया बयान अबू आजमी ने आरोप लगाया कि देश में मुस्लिम समुदाय को कई मुद्दों पर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि ऐसी नीतियां देश को कमजोर और विभाजित करने का काम कर सकती हैं। हालांकि, उनके इन आरोपों पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने की संभावना है। अबू आजमी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय लोगों की मदद के लिए खुले हैं।

मीरा रोड में बाल-बाल बचे चार लोग, तेज रफ्तार एसयूवी ने सड़क किनारे खड़े लोगों को मारी टक्कर...

मीरा रोडः मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में हिट-एंड-रन की एक खतरनाक घटना सामने आई है, जिसने सड़क सुरक्षा और पैदल चलने वालों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। जेपी बैक रोड इलाके के पास सड़क किनारे खड़े चार लोग एक तेज रफ्तार एसयूवी की चपेट में आने से बाल-बाल बच गए। घटना इतनी भयावह थी कि कुछ सेकंड के अंतर से बड़ा हादसा टल गया। पूरी घटना एक अन्य वाहन के डैशकैम में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने लापरवाह ड्राइविंग और सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं।

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क किनारे कुछ लोग खड़े हुए थे। इसी दौरान अचानक एक एसयूवी तेज गति से उनकी ओर आती दिखाई देती है। वाहन इतनी तेजी से उनके करीब पहुंचता है कि वहां मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। वीडियो में दिखाई देता है कि एसयूवी सड़क किनारे खड़े लोगों के बेहद करीब से निकलती है। हालांकि, किसी तरह चारों लोग सुरक्षित बच जाते हैं और एक बड़ा हादसा होने से टल जाता है।

इस घटना का वीडियो इंस्टाग्राम कम्युनिटी पेज 'जेम्सऑफएमबीएमसी' की ओर से साझा किया गया है। फुटेज में दिख रहे टाइमस्टैम्प के अनुसार, यह घटना सोमवार शाम की बताई जा रही है। सड़क सुरक्षा पर उठे सवाल इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि शहर और उपनगरों में तेज रफ्तार वाहन चलाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे पैदल यात्रियों और सड़क किनारे खड़े लोगों की जान खतरे में रहती है।

मीरा रोड जैसे तेजी से विकसित हो रहे इलाकों में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में यातायात नियमों का पालन और तेज गति पर नियंत्रण बेहद जरूरी हो गया है। स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि ऐसे क्षेत्रों में ट्रैफिक निगरानी बढ़ाई जाए और लापरवाही से वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर 4 ए, फ्लोर-जीआरडी, 29 डी, शबन हाउस, वंजावाडी लेन, माहिम वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400016 से प्रकाशित किया। मोबाइल नं 998777 5650, Email-editor@rokthoklekhani.com